दिल्ली में अवैध होटल में भीषण आग, 21 की मौत

दो साल से 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' नाम से अवैध तरीके से चल रहा था रेस्तरां व होटल

बिल्डिंग से कूदने वाले और झुलसे 37 लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा इलाज

बेसमेंट से लगी आग भूतल पर किचन होने के कारण तेजी से फैलने की आशंका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

देश की राजधानी एक बार फिर कानून की अनदेखी और लापरवाही की आग में झुलसी। बुधवार की सुबह एक होटल में भीषण आग लगने से 11 विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। हादसे के दौरान बिल्डिंग की खिड़कियों से नीचे कूदने, धुएं में दम घुटने और आग में झुलसे करीब 37 अन्य लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की स्थिति गंभीर है।

राष्ट्रीय राजधानी के पाश मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में स्थित 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' नाम से चले रहे रेस्तरां एवं होटल में हुए अग्निकांड में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की है आशंका है।

जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसमें नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध तरीके से रेस्तरां और होटल चलाया जा रहा था। भूतल पर रेस्तरां चल रहा था। आशंका है कि आग लगने की शुरुआत भूतल से हुई, जहां किचन होने के कारण आग तेजी से फैल गई।

करीब 150 गज में बनी बिल्डिंग में बाहर आने जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी। इसमें कोई भी आपातकालीन द्वार नहीं था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या व लापरवाही से हुई मौत आदि धाराओं में केस दर्ज कर होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मरने वाले 10 भारतीय गुरुग्राम और राजस्थान के हैं, जिनकी पहचान हो गई है लेकिन विदेशी नागरिकों की पहचान में दिक्कत आ रही है। पहचान होने के बाद संबंधित देशों के दूतावासों व उच्चायोग के जरिये उनके स्वजनों को सूचना दी जाएगी अथवा पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिए जाएंगे।

पुलिस को आग लगने की सूचना सुबह करीब 8.48 बजे मिली। इसके बाद कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि पहुंच गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी उससे महज कुछ ही दूरी पर मैक्स अस्पताल है। बताया जाता है कि जो लोग इस अस्पताल में इलाज के लिए आते थे, अधिकतर उनके तीमारदार अथवा मरीज भी इस होटल में ठहरते थे।

- बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या, मृतको की पहचान में आ रही है दिक्कत

150 गज में बनी बिल्डिंग में आने-जाने के लिए केवल एक ही तरफ थीं सीढ़ियां

15 गाड़ियों को आग बुझाने में लग गए करीब दो घंटे

10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए लोगों को बाहर निकालने में

10 जान गंवाने वालों में हरियाणा व राजस्थान के थे

नहीं लिया सबक

अग्निकांड	वर्ष	मौतें
उपहार सिनेमा	1997	59
नंदनगरी	2011	14
करोल बाग	2012	17
अनाज मंडी	2019	43
मुंडका	2022	27
विवेक विहार	2024	7

मालवीय नगर के हौजरानी स्थित गेस्ट हाउस में लगी आग। सौ. वीडियो ग्रैब

छह की थी अनुमति, बने हैं 23 कमरे

यह बिल्डिंग अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर की थी। पहले इसके भूतल पर खादी कपड़े की दुकान थी। करीब दो साल पहले लवकेश बजाज ने इसे खरीदकर पांच मंजिल बनाकर इसमें रेस्तरां और होटल खोल लिया था। इसमें कुल 23 कमरे बने हैं, जबकि अनुमति मात्र छह कमरों की थी। पांच मंजिल इमारत के बेसमेंट में कुछ कमरे थे।

सड़कों पर बिछाए गद्दे पर लोग खिड़कियों से कूदे

होटल के सामने रियाजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की गद्दे की दुकान खुली थी। उसके सारे गद्दे को होटल के दोनों तरफ सड़कों पर बिछा दिए गए और पहली से लेकर पांचवीं मंजिल की खिड़कियों से अंदर फंसे लोगों को खिड़कियों से कूदने के लिए कहा गया। कुछ को स्थानीय लोगों ने सीढ़ियों के सहारे भी खिड़कियों से बाहर निकाल लिया। पास में मैक्स अस्पताल होने के कारण अधिकतर लोगों को तुरंत वहीं पहुंचाया गया।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी शोकाकुल स्वजन को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

टीएमसी दो फाड़, 58 विधायकों वाले गुट के ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- तृणमूल के 28 साल के इतिहास में पहली बार पार्टी में औपचारिक विभाजन
- असंतुष्ट विधायकों के पत्र के बाद विप अध्यक्ष ने दी बागी गुट को मान्यता

देश की राजनीति में पूरी पार्टी के अपने सर्वोच्च नेता के खिलाफ खड़े होने की घटना एक बार फिर दोहराई गई, जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन के एक महीने के भीतर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में दो फाड़ हो गई। पार्टी के नवनिर्वाचित 80 विधायकों में से 58 ने एक अलग गुट बनाकर ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता घोषित कर दिया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ बोस ने इस गुट के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष और अखरुजम्मान को मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दे दी।

ऋतब्रत की अगुआई वाले गुट ने खुद को "वास्तविक तृणमूल" बताया। बागी गुट का नेतृत्व कर रहे टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। इसके तहत विधायक दल के उपनेता के तौर पर जावेद अहमद खान, संदीपन साहा, सबीना यासमीन और शिउली साहा को मान्यता देने का अनुरोध किया, जिसे कुछ घंटे के भीतर ही स्पीकर रथींद्रनाथ बोस ने मंजूरी दे दी। विधानसभा सचिव ने ऋतब्रत को विपक्ष के नेता के लिए निर्धारित कक्ष की चाबी भी सौंप दी। इस फैसले के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 28 साल के इतिहास में पहली बार पार्टी में औपचारिक विभाजन हो गया।

कोलकाता में बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते ऋतब्रत बनर्जी (मध्य में)। प्रेट्र

दरअसल, बंगाल में महाराष्ट्र के 'एकनाथ शिंदे माडल' को दोहराने का प्रयास हुआ है। महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने सत्ता तक पहुंचने के लिए शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ ही नहीं, बल्कि पूरी पार्टी पर कब्जा जमा लिया था। इससे पहले 1995 में चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर और तेलुगु देसम के सीएम एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत करते हुए पूरी पार्टी को अपने हाथ में ले लिया था।

विवाद की शुरुआत ऋतब्रत बंद्योपाध्याय और संदीपन साहा की उस शिकायत से हुई, जिसमें विपक्ष के नेता के समर्थन से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने का आरोप लगाया गया। शिकायत के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच सीआइडी कर रही है।

ममता बनर्जी ने शोभनदेब को बनाया था नेता प्रतिपक्ष पेज>>4

साफ की तस्वीर

केंद्रीय बैंक और पीआइबी दोनों ने ब्लूमबर्ग की खबरों का किया खंडन, आरबीआइ ने कहा, विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार की हिस्सेदारी बढ़ी, हालांकि, 22 मई को स्वर्ण भंडार की भौतिक स्थिति पर स्पष्टता नहीं

नहीं बेचा 12 अरब डालर का स्वर्ण भंडार : आरबीआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आरबीआइ ने मीडिया में आई उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने लगभग 12 अरब डालर का स्वर्ण भंडार बेच दिया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इसे झूठी खबर बताते हुए स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक की तरफ से इस तरह का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआइबी) द्वारा किए गए फैक्ट चेक और आरबीआइ की तरफ से अलग-अलग प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की तरफ से प्रसारित रिपोर्ट को गलत करार दिया गया है। उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि आरबीआइ ने मई 2026 के मध्य तक सोना बेचकर विदेशी मुद्रा आस्तियों का मजबूत किया है।

आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के अंत में 13.92 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2026 को 16.70 प्रतिशत और 22 मई 2026 को 16.85 प्रतिशत हो गई है। भौतिक स्वर्ण भंडार भी अपरिवर्तित है। आरबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक दो मई, 2025 को उसके पास 879.58 मीट्रिक टन सोना जो 24 अप्रैल, 2026 को 880.52 मीट्रिक टन हो गया है। हालांकि, इस दौरान सोने की कीमत में भारी वृद्धि हुई है लिहाजा भंडार का कुल मूल्य 6,91,478 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,33,076 करोड़ रुपये हो गया है। आरबीआइ की उक्त बातें सही हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में 22 मई को स्वर्ण भंडार की मात्रा का जिक्र है। दरअसल, आरबीआइ ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वह 24 अप्रैल तक के हैं। वैसे आरबीआइ के ताजा साप्ताहिक आंकड़ों (22 मई 2026) के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का मूल्य 46,156 करोड़ रुपये घटकर 10,98,889 करोड़ रुपये रह गया है। यह कमी किसी भौतिक बिक्री के चलते हुई या अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से है, यह स्पष्ट नहीं है। यह स्थिति तब साफ होगी तब आरबीआइ यह बताएगा कि 22 मई को उसके पास कितना टन सोना है और क्या यह 24 अप्रैल, 2026 के बराबर है या नहीं।

प्रतीकात्मक

880.52 मीट्रिक टन सोने में से 680 टन से अधिक देश के अंदर है रखा

आरबीआइ पिछले कुछ सालों में शुद्ध सोने का खरीदार रहा है। मार्च 2026 तक कुल 880 .52 मीट्रिक टन सोने में से 680 टन से अधिक देश के अंदर रखा गया है, जो आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा की मजबूती का प्रमाण है।

सोने की खरीद-बिक्री बाजार स्थितियों के अनुरूप सामान्य रणनीति का हिस्सा : दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों की तरफ से समय समय पर सोने की खरीद-बिक्री होती रहती है। यह विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर को बनाए रखने, तरलता प्रबंधन या बाजार स्थितियों के अनुरूप सामान्य रणनीति का हिस्सा होता है। हाल के महीनों में रूस और तुर्किए के केंद्रीय बैंकों ने स्वर्ण संबंधी समायोजन किए हैं। रूस ने 2025 से युद्ध खर्च के लिए सोना बेचा है, जिससे उसका भंडार चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तुर्किए ने लीरा की रक्षा के लिए सोने का उपयोग किया, जिसमें सैकड़ों टन सोने को दूसरे देशों में गिरवी रखना भी शामिल हैं।

समुद्री रणनीति का प्रमुख केंद्र ग्रेट निकोबार

डीके जोशी

ग्रेट निकोबार परियोजना आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वैश्विक प्रभाव के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है

सदियों पहले कौटिल्य ने कहा था कि 'जो राज्य अपनी सीमाओं, साझेदारियों और व्यापार मार्गों की सुरक्षा नहीं करता, वह अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं रख सकता।' कौटिल्य की यह सीख आज कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज देशों की परीक्षा केवल उनकी अर्थव्यवस्था के आकार या सैन्य ताकत से नहीं हो रही, बल्कि इससे हो रही है कि वे भूगोल को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, भविष्य का कितना सही अनुमान लगाते हैं और अवसर के खतरे में बदलने से पहले कितनी तेजी से निर्णय लेते हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए ऐसी ही एक बड़ी परीक्षा है। इस क्षेत्र को दशकों से उसके हाल पर छोड़कर उपेक्षित बना दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भी लंबे समय तक भारत का सामरिक सोच मुख्य रूप से स्थल-आधारित रहा। जबकि इस दौरान दुनिया बहुत बदल भी गई है।

ग्रेट निकोबार भारत की अग्रिम समुद्री चौकी है। इसके प्रस्तावित विकास को केवल एक अवसंरचना परियोजना के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह मात्र एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, टाउनशिप या बिजली संयंत्र बनाने का प्रश्न नहीं है। वास्तव में यह भारत के लिए एक परीक्षा है कि क्या भारत इस विलक्षण भौगोलिक बढ़त को सामरिक शक्ति में रूपांतरित करने के लिए तैयार है या नहीं। ग्रेट निकोबार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 910 वर्ग किलोमीटर है। प्रस्तावित परियोजना का कुल क्षेत्रफल 166.10 वर्ग किमी है, जो समूचे द्वीप समूह के कुल क्षेत्रफल का केवल लगभग दो प्रतिशत है। इसमें से 130.75 वर्ग किमी वन भूमि को परियोजना के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है, जो द्वीप समूह के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1.82 प्रतिशत है। यह हिस्सा दक्षिण-पूर्व एशिया के निकट स्थित है तथा मलक्का स्ट्रेट, 60 चैनल, सुंडा स्ट्रेट और लोंबोक स्ट्रेट जैसे प्रमुख वैश्विक समुद्री मार्गों के समीप आता है। सामरिक दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र को भारत की पूर्वी समुद्री चौकी की संज्ञा दी जा सकती है। इसका महत्व तब और स्पष्ट हो जाता है जब इसे केवल भूभाग के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि महासागरीय रणनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र अब एक बड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुका है, उसे देखते हुए भविष्य की रणनीति के लिहाज से इस क्षेत्र की महत्ता और बढ़ गई है।

हाल की एक महत्वपूर्ण प्रगति यह है कि अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ने वाली दशकों पुरानी कैनल परियोजना को स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब लगभग 90 किमी लंबे मल्टी मोडल लैंड ब्रिज की योजना अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। यह परियोजना टैंथ पैरेलल के साथ दो गहरे समुद्री बंदरगाहों को जोड़ेगी। एक अंडमान सागर के किनारे रणोंग में और दूसरा थाईलैंड की खाड़ी के किनारे चुंफ्रोन में। इसके अलावा हाई स्पीड रेल, मल्टी लेन सड़क, तेल एवं गैस के लिए ऊर्जा पाइपलाइनें तथा वायु एवं डिजिटल ग्रिड भी प्रस्तावित हैं। ये सभी कारक हिंद प्रशांत व्यापार मार्गों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और आर्थिक शक्ति का केंद्र सीधे अंडमान बेसिन की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सामुद्रिक चोक पाइंट्स में से एक है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और अत्यंत मूल्यवान ऊर्जा संसाधनों की आवाजाही तथा वैश्विक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ग्रेट निकोबार की गलाथिया खाड़ी 60 चैनल से लगभग 45 किमी दूर है, जो मलक्का स्ट्रेट को अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों से जोड़ती है। अनुमान है कि हर साल लगभग एक लाख जहाज मलक्का स्ट्रेट 60 चैनल मार्ग से गुजरते हैं। मलक्का, सुंडा और लोंबोक जैसे सामरिक चोक पाइंट्स के निकट होने के कारण यह द्वीप भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त प्रदान करता है। कोई भी गंभीर सामुद्रिक शक्ति ऐसे भौगोलिक तथ्यों की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती।

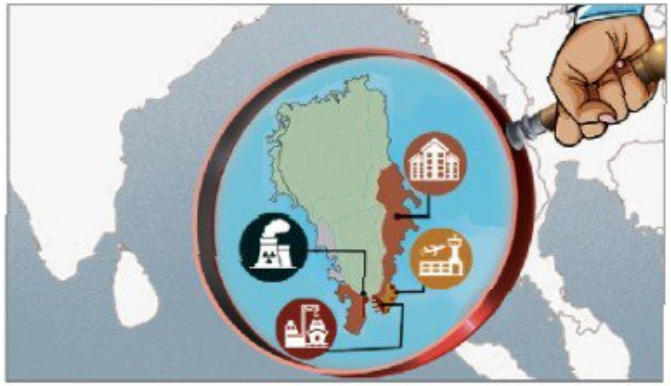

अवधेश राजपूत

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने समुचित जांच-पड़ताल और आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह स्वीकार किया कि यह परियोजना केवल द्वीप और उसके आसपास के सामरिक क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामुद्रिक शक्ति केवल भूगोल से नहीं बनती, वह भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग करने की आवश्यक क्षमता विकसित करने से निर्मित होती है। ग्रेट निकोबार भारत को यह सब एक संतुलित एवं विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण के साथ साकार करने का अवसर प्रदान करता है। यह व्यापार को बढ़ावा दे सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है। विदेशी ट्रांसशिपमेंट केंद्रों पर निर्भरता कम कर सकता है। साथ ही भारत की सामुद्रिक पहुंच को विस्तारित कर सकता है तथा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक सामरिक मंच के रूप में कार्य कर सकता है। ग्रेट निकोबार में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत की उस सामग्री पर निर्भरता को कम कर सकता है, जिसे वर्तमान में विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से ट्रांसशिप किया जाता है। इस परियोजना से आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और भारत को अपनी सामग्री की आवाजाही पर अधिक नियंत्रण एवं निश्चितता प्राप्त होगी।

निःसंदेह ग्रेट निकोबार पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इस स्तर की किसी भी परियोजना को पारिस्थितिकीय सावधानी, वैज्ञानिक निगरानी और हरसंभव उपायों के साथ लागू किया जाना चाहिए। विकास लापरवाह नहीं हो सकता, लेकिन पर्यावरणीय संवेदनशीलता को सामरिक चिंतन पर स्थायी वीटो का आधार भी नहीं बनाया जा सकता। इस संदर्भ में वास्तविक चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने की दिशा में संतुलन साधने की है।

(लेखक अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष तथा पूर्व नौसेना प्रमुख हैं)
response@jagran.com

आजकल

कैलाश बिश्नोई
शिक्षा मामलों के जानकार

डिजिटल मूल्यांकन की कसौटी पर सीबीएसई

देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा संस्था सीबीएसई एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। केंद्र सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब आन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, मूल्यांकन की विश्वसनीयता और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। लाखों विद्यार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां मांगना, स्कैन कापियों की गुणवत्ता पर आपत्तियां तथा मूल्यांकन संबंधी शिकायतें इस बहस को और व्यापक बना चुकी हैं। यह केवल एक तकनीकी विवाद नहीं, बल्कि परीक्षा प्रशासन की संस्थागत क्षमता की भी परीक्षा है

डिजिटल व्यवस्था से सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की कापी के मूल्यांकन पर उठे हैं गंभीर सवाल। प्रतीकात्मक

वर्ष 2026 में सीबीएसई ने बारहवीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया गया तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को स्क्रीन आधारित बनाया गया। उद्देश्य था- मूल्यांकन की दक्षता बढ़ाना, मानवीय त्रुटियों को कम करना, परिणाम प्रक्रिया को तीव्र बनाना तथा परीक्षा प्रशासन को डिजिटल रूपांतरण की दिशा में आगे ले जाना। किंतु परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने धुंधली स्कैन प्रतियों, उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान संबंधी त्रुटियों, मूल्यांकन की शुद्धता तथा तकनीकी अवरोधों को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए।

यह विवाद वस्तुतः तकनीक और शिक्षा प्रशासन के अंतर्संबंध को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। शिक्षा में डिजिटलीकरण समय की आवश्यकता है, किंतु शैक्षणिक नवाचारों की सफलता केवल साफ्टवेयर या प्लेटफार्म से निर्धारित नहीं होती। उसके लिए चरणबद्ध परीक्षण, हितधारकों की सहभागिता, क्षमता निर्माण तथा प्रक्रियागत परिपक्वता अनिवार्य होती है। यदि अधिगम उपलब्धियों के आकलन से जुड़ी किसी व्यवस्था में विद्यार्थियों को अपने मूल्यांकन पर ही संदेह होने लगे, तो प्रश्न केवल तकनीकी खामी का नहीं रह जाता, बल्कि शैक्षिक शासन, नीति क्रियान्वयन और सार्वजनिक विश्वास का बन जाता है। यही कारण है कि आन-स्क्रीन मार्किंग का यह प्रकरण शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की संभावनाओं के साथ-साथ उसकी सीमाओं और चुनौतियों पर गंभीर पुनर्विचार की मांग करता है।

विडंबना यह है कि नई शिक्षा नीति लगातार क्षमता निर्माण, साक्ष्य आधारित निर्णय और संस्थागत तैयारी पर बल देती है, लेकिन आन-स्क्रीन मार्किंग के अनुभव ने इन आदर्शों और व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच मौजूद दूरी को उजागर कर दिया। तकनीक अपने आप में न तो समाधान है और न समस्या। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी दूरदर्शिता, कितनी तैयारी और कितनी संवेदनशीलता के साथ लागू किया गया। यदि लाखों विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता के बजाय आशंकाएं और संतोष की बजाय संदेह उत्पन्न होने लगें, तो आत्ममंथन केवल विकल्प नहीं बल्कि संस्थागत दायित्व बन जाता है।

इस पूरे विमर्श का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम शिक्षक समुदाय से जुड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर विभिन्न शैक्षणिक आयोगों की अनुशंसाओं तक शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना गया है। दुर्भाग्य से व्यावहारिक स्तर पर अनेक बार उसे केवल क्रियान्वयन तंत्र का एक घटक समझ लिया जाता है। आन-स्क्रीन मूल्यांकन इसका उदाहरण है। उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल परीक्षण सुनने में भले सरल लगे, लेकिन मूल्यांकन शास्त्र की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। यदि शिक्षक को पर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और कार्यानुकूल वातावरण उपलब्ध न कराया जाए तो मूल्यांकन की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। शिक्षा में गुणवत्ता केवल नीतिगत घोषणाओं से नहीं आती। वह क्षमता निर्माण, संसाधन समर्थन और व्यावसायिक विकास की सतत प्रक्रिया से विकसित होती है।

इस विवाद का सबसे संवेदनशील और व्यापक पक्ष विद्यार्थी हैं। बारहवीं कक्षा का परिणाम केवल एक अंकपत्र नहीं होता, बल्कि उच्च शिक्षा, व्यावसायिक अवसरों, छात्रवृत्तियों और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की दिशा निर्धारित करने वाला दस्तावेज होता है। ऐसे में यदि मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर संदेह उत्पन्न हो जाए तो समस्या प्रशासनिक दायरे से निकलकर विश्वास के संकट में बदल जाती है। किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है। विद्यार्थी कठिन प्रश्नपत्र स्वीकार कर सकता है, अपेक्षा से कम परिणाम भी स्वीकार कर सकता है, किंतु वह मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे प्रश्नों को स्वीकार नहीं कर सकता।

हालांकि इस पूरे प्रकरण को केवल विफलता के आख्यान के रूप में देखना उचित नहीं होगा। डिजिटल मूल्यांकन की अवधारणा में अनेक संभावनाएं निहित हैं। इससे उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा बेहतर हो सकती है, मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी सुदृढ़ हो सकती है, डाटा आधारित विश्लेषण संभव हो सकता है और भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए आधार तैयार हो सकता है। इसलिए समाधान तकनीक से पीछे हटने में नहीं, बल्कि उसके अधिक परिपक्व और उत्तरदायी उपयोग में निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यापक पायलट परियोजनाओं के माध्यम से प्रणाली का परीक्षण किया जाए, शिक्षकों के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएं, साफ्टवेयर डिजाइन में विषय विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा स्वतंत्र शैक्षणिक आडिट की व्यवस्था स्थापित की जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थियों के हित को संस्थागत प्रतिष्ठा से ऊपर रखा जाए। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल परीक्षाओं का संचालन नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास का निर्माण है।

आज सीबीएसई के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती किसी तकनीकी प्लेटफार्म की नहीं, बल्कि उसी विश्वास को पुनर्स्थापित करने की है जिस पर करोड़ों विद्यार्थियों और अभिभावकों की आकांक्षाएं टिकी हुई हैं। तकनीक को सुधारा जा सकता है, प्रक्रियाओं को पुनर्गठित किया जा सकता है, लेकिन विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए संवेदनशील नेतृत्व, पारदर्शी संवाद और उत्तरदायी प्रशासन की आवश्यकता होती है। शिक्षा में आधुनिकता का स्वागत होना चाहिए, किंतु परिपक्वता और तैयारी के साथ। अन्यथा डिजिटल व्यवस्था की छोटी सी त्रुटि भी अधिगम न्याय और मूल्यांकन विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्नचिह्न छोड़ सकती है।

परीक्षा व्यवस्था में सुधारों का नया दौर

पिछले एक दशक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केवल परीक्षाओं की प्रक्रिया नहीं बदली है, बल्कि शिक्षा को देखने और समझने के नजरिये में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किए गए सुधारों का उद्देश्य छात्रों को रटंत शिक्षा की सीमाओं से बाहर निकालकर उन्हें समझ, कौशल और व्यावहारिक क्षमता आधारित सीखने की ओर ले जाना है। लंबे समय तक भारतीय बोर्ड परीक्षाओं की सबसे बड़ी आलोचना यह रही कि वे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति तो मापती हैं, लेकिन उनकी सोचने, विश्लेषण करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का पर्याप्त आकलन नहीं कर पातीं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कंपीटेंसी आधारित प्रश्नों का दायरा बढ़ाया है।

दसवीं की बोर्ड परीक्षा में दो अवसर देने का निर्णय भी शिक्षा सुधारों के इसी नए सोच का हिस्सा है। भारतीय समाज में परीक्षा अक्सर एक ऐसे निर्णायक मोड़ के रूप में देखी जाती रही है, जहां एक दिन का प्रदर्शन पूरे भविष्य का फैसला कर देता है। सुधार परीक्षा और सर्वश्रेष्ठ स्कोर को मान्यता देने की व्यवस्था इस दबाव को कम करती है। यह छात्रों को यह विश्वास दिलाती है कि शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि निरंतर सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। डिजिटल तकनीक के उपयोग ने भी परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दी है। डिजिलाकर, अपार आइडी और विभिन्न आनलाइन प्लेटफार्मों ने रिकार्ड प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाएं भी इसी परिवर्तन का हिस्सा हैं। हालांकि हाल के अनुभवों ने यह भी स्पष्ट किया है कि तकनीकी सुधारों की सफलता केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि तैयारी, प्रशिक्षण और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए सुधारों की दिशा जितनी महत्वपूर्ण है, उनकी गति और तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

सीबीएसई द्वारा कौशल शिक्षा और व्यावसायिक विषयों को बढ़ावा देना भी एक दूरदर्शी कदम माना जा सकता है। बदलती अर्थव्यवस्था में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है। रोजगार और जीवन दोनों के लिए कौशल की आवश्यकता बढ़ी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्यमिता, योग और अन्य स्किल आधारित विषयों को मुख्यधारा में लाकर शिक्षा को अधिक प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया है। सिलेबस का तर्कसंगत पुनर्गठन और पाठ्यचर्या में बदलाव भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। शिक्षा तब अधिक प्रभावी होती है जब छात्र विषय को समझे, उससे जुड़े और उसे जीवन में लागू कर सके।

इन सभी सुधारों के केंद्र में एक महत्वपूर्ण विचार दिखाई देता है... शिक्षा को परीक्षा केंद्रित व्यवस्था से सीखने केंद्रित व्यवस्था में बदलना। यह परिवर्तन आसान नहीं है और इसके सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने की आवश्यकता बनी हुई है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षा का भविष्य केवल अधिक अंक प्राप्त करने में नहीं, बल्कि बेहतर नागरिक और सक्षम मानव संसाधन तैयार करने में निहित है। सीबीएसई के हालिया सुधारों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये परिवर्तन अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि उस लंबी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो भारतीय शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी, कौशल आधारित और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

(कैलाश बिश्नोई)

कैबिनेट का फैसला • कैंसर-हार्ट जैसी बीमारियों के लिए सरकार देगी पैसा

मिडिल क्लास को 'कवच'...अब 4 लाख की आय पर भी मुफ्त इलाज

▪ इलाज के लिए अब नहीं बिकेगा घर-जेवर... लाखों परिवारों को जीवनदान

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार सरकार ने मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। सरकार ने 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए आय की सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर सीधे 4 लाख सालाना कर दिया है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब राज्य का वह मध्यम वर्ग भी सरकारी सहायता का हकदार होगा, जो अब तक 'अमीर' मानकर योजना से बाहर रखा गया था। अब कैंसर, हृदय रोग और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जानलेवा बीमारियों के सामने मध्यम वर्गीय परिवारों को घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों नए परिवारों को सुरक्षा कवच मिल गया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 13 अहम फैसलों पर मुहर लगी।

बिहार सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनकी मासिक आय लगभग 33,000 रुपये है। पहले ढाई लाख की सीमा के कारण निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार कैंसर, हृदय रोग और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज के दौरान मदद के योग्य नहीं माने जाते थे। आय सीमा में 1.50 लाख की बढ़ोतरी होने से अब आवेदकों की संख्या में भारी उछाल आने की उम्मीद है।

प्रशासनिक प्रक्रिया और बजट पर बढ़ेगा दबाव

स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश के लागू होने के बाद अब पटना समेत सभी जिलों के सिविल सर्जन कार्यालयों और अनुशंसित अस्पतालों में आवेदनों की स्क्रीनिंग का दायरा बदल जाएगा। हालांकि, नीतिगत स्तर पर आय सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के बजट को आवंटित करने और अस्पतालों को समय पर भुगतान करने की होगी, ताकि मरीजों को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि वास्तविक इलाज मिल सके।

भास्कर एनालिसिस क्यों जरूरी था यह फैसला

अब तक मध्यम वर्ग 'त्रिशंकु' की स्थिति में था, न वह इतना गरीब था कि मुफ्त इलाज पाए और न इतना अमीर कि लाखों का खर्च उठा सके।

पुरानी व्यवस्था: सालाना आय 2.50 लाख तक थी, जिससे केवल अत्यंत गरीब ही कवर होते थे।

नई व्यवस्था: अब 4 लाख तक की आय वाले भी शामिल हैं, जिससे इलाज के अभाव में दम तोड़ने वाले मामलों में भारी कमी आएगी।

किस बीमारी में किस तरह के इलाज के लिए मदद

कैंसर- शल्य चिकित्सा समेत हर तरह के इलाज **हृदय रोग-**शल्य चिकित्सा, डीवीआर, एमवीआर, पेस मेकर, बैलूनिंग, पीटीसीए, एसडी। **एड्स-** हर तरह का इलाज। **कुल्हा या घुटना का रिप्लेसमेंट** - इससे संबंधित हर तरह के इलाज। **स्पाइनल सर्जरी-** हर तरह का खर्च। **वेस्कुलर सर्जरी-** धमनियों और नसों से जुड़ी समस्या की सर्जरी। **बोन मैरो ट्रांसप्लांट-** बोन मैरो को बदलने की प्रक्रिया।

निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता वाली समिति लेती है फैसला... मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए पात्रों का चयन निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता वाली समिति करती है। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को सहायता का भुगतान सीधे अस्पताल को होता है। रोगी को बिहार का नागरिक और इलाज सरकार के अस्पताल या सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल में होना चाहिए।

कैबिनेट के अन्य 5 बड़े फैसले

भोजपुर में एक्वा पार्क: बिहार के भोजपुर जिले में 31.20 करोड़ रुपये की लागत से 'इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क' की स्थापना की जाएगी, जिससे मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा।

दरभंगा एम्स का रास्ता साफ: एम्स के लिए चयनित भूखंड को समतल करने हेतु पास की नदियों से निकाली गई मिट्टी/गाद का उपयोग किया जाएगा।

नबीनगर में नया आईटीआई: औरंगाबाद के नबीनगर में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा, जहां 5 व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए 38 नए पद सृजित किए गए हैं।

बिजली उपभोक्ताओं को राहत: नॉर्थ-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के पद सृजित होंगे।

खाद्य प्रसंस्करण पर जोर: पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का विस्तार सितंबर 2026 तक किया गया है, जिसके लिए 16451.60 लाख की स्वीकृति दी गई है।

21 dead in Delhi hotel fire, foreigners among victims

At least 47 people pulled out from the hotel which did not have clearance from fire department, say officials; owner of the building held; month-long drive to check fire-safety norms in buildings in city

Shrimansi Kaushik
Suruchi Kumari
NEW DELHI

Furious flames: People attempting to douse the fire at the hotel in Malviya Nagar on Wednesday. AP

Twenty-one people, foreign nationals among them, died in a blaze that ripped through a hotel in south Delhi's Malviya Nagar on Wednesday morning, officials said. At least 47 persons were pulled out from the fire and taken to nearby hospitals for treatment.

According to the police, of the deceased, 12 were foreign nationals and rest were Indians.

Officials said the Flourish Stay bed-and-breakfast facility was operating without clearance from the fire department. Lovkesh Bajaj, the owner of the building, was apprehended by the police. A first information report (FIR) was registered against him under Sections 105 (culpable homicide not amounting to murder) and 326 (mischief by fire) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

According to the Delhi police, the fire started at the ground floor of the six-storey building and spread to the upper floors.

Many people trapped inside the building began jumping out in desperation onto mattresses laid out on the ground by the local people trying to rescue them, eyewitnesses said.

CONTINUED ON
» **PAGE 10**
RELATED REPORTS ON
» **PAGES 2, 10**

Assembly poll results that recast the political landscape

M.K. Narayanan

Former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal

Outcomes in the recent Assembly elections in Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam demand careful introspection. The results in Assam and Kerala were not unexpected, but Tamil Nadu and perhaps West Bengal, appear to signal the shape of things to come, and of the role of Gen Z in this respect.

In Tamil Nadu, a close to 60-year-old duopoly of the Tamil Dravidian parties was ended by a party headed by a relatively unknown newcomer, who had few pretensions to any ideology. Complementing the upheaval in Tamil Nadu was the eclipse of the 'people's leader' in West Bengal, Mamata Banerjee, who only a few years back had toppled a Marxist conglomerate that had remained entrenched for nearly three decades.

The script in Assam and West Bengal

Assam, adhering to the script, produced an expected result, *viz.*, a Bharatiya Janata Party (BJP), or rather more appropriately a Himanta Biswa Sarma victory, who notched up his second consecutive success. Victory was a foregone conclusion, given the extent of communal politics prevailing in the State and the redrawing of constituency boundaries, which reduced the number of Muslim-majority seats and put the BJP's rivals such as the Congress and the All India United Democratic Front at a disadvantage. This time Mr. Sarma also ensured the eclipse of the remnants of Assam's political past, as also the legacies of Hiteswar Saikia, Tarun Gogoi and Bhumidhar Barman and the era of Congress rule.

More significantly perhaps, in a State with 34% Muslim population, he ensured that not one Muslim representative was elected as a member of the majority BJP party, even as 18 of the 19 Opposition Congress MLAs elected were Muslims. While some form of ethnic cleansing had been in evidence in Assam for some time, ostensibly to eliminate 'illegals' (essentially 'Bangladeshi Muslims'), the wider implications of not a single Muslim being elected as part of the ruling echelon is worth examining in some detail. At one level it would seem a travesty of India's claims to be a multi-religious, multi-cultural civilization.

The Assembly elections in West Bengal witnessed the BJP coming to power in the State for the first time. Bengal appeared to be a State under siege during the two phases of polling, with the deployment of over 2,500 companies of the Central Armed Police Forces, ostensibly to maintain order, even though no major law-and-order issues were reported. Together with the removal of several lakh voters from the electoral rolls following the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, this created a surreal atmosphere in the State during the elections.

Explaining the outcome in Bengal may appear relatively straightforward, but understanding the factors behind the BJP's success is less so. The standard explanation for Ms. Banerjee's eclipse is that, after 15 years in office, her regime had ossified. Its perceived overreliance on the Muslim vote – more specifically on 'returnees from erstwhile East Bengal' – allegedly provoked adverse reactions.

Coupled with charges of administrative apathy and a lack of employment opportunities, this is said to have contributed to a consolidation of the Hindu vote against her. Interestingly, despite the existence of a 27% Muslim vote in Bengal, not a single Muslim was elected as part of the ruling alliance, while the Opposition returned over 35 Muslim MLAs in its tally of 86 seats. The implications of this development merit careful consideration.

Other reasons being adduced for the defeat of Ms. Banerjee and the All India Trinamool Congress, are the tardy response of the erstwhile Chief Minister and her coterie to the R.G. Kar Hospital imbroglio, the lingering shadow of Singur and Nandigram, and a failure to recognise Gen Z's aspirations for better employment opportunities in a shrinking job market. Taken together, these factors allowed the BJP to capitalise on a prevailing anti-Mamata and anti-Trinamool sentiment.

The recent election results in four key States have revealed shifting voter priorities and challenged established political certainties

Upending Dravidian dominance

If the change in Bengal could be compared to a political earthquake, the real tsunami was in Tamil Nadu, where close to six decades of 'Dravidian' rule was swept aside by the Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) headed by a political neophyte, C. Joseph Vijay. Rationalism and caste took a back seat, concerns about North Indian domination seemed to recede to the background, even as established Dravidian parties such as the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam bit the dust. The erstwhile Chief Minister, from the DMK, became a victim of the tidal wave of youth power.

The 1967 eclipse of the Congress party by the DMK under C.N. Annadurai hardly bears comparison with the achievement of Mr. Vijay's two-year-old party, despite its lack of a well-defined political construct. The electorate only appeared determined to remove decades of duopoly of the DMK and AIADMK, viewing Mr. Vijay as a breath of fresh air in a region long consumed by anti-Delhi beliefs and ideas. Mr. Vijay's TVK promised to retain the model of social justice and the broadly secular welfare-friendly policies of the previous regime, but his emergence denotes the beginnings of the end of 'Dravidianisation' of politics in the State.

The change in Tamil Nadu does suggest that southern politics, despite a strong anti-Delhi thrust, may be in for a change. Even as the ideas and concepts of Periyar, Annadurai and Karunanidhi are likely to remain, many concepts and beliefs could alter, and this might well provide space for other ideologies to enter. The reasons for Chief Minister M.K. Stalin's defeat in a constituency that he had assiduously nursed for years, and having provided relatively competent leadership to the State overall, does call for a deeper study as its implications are huge. Meanwhile, Mr. Vijay is clearly the 'trumpeter' of change, but he may not necessarily be the future.

The Kerala result

Elections in Kerala followed a more traditional pattern of alternating between a Congress-led coalition and a Marxist-led Left Front. In 2021, the Communist Party of India (Marxist), under Pinarayi Vijayan, had bucked this trend, and continued in office with its alliance for a further five years, but Mr. Vijayan was to be the main reason for the debilitating defeat of the CPI(M)-led Front in the recent Assembly elections. In the event, a Congress-led United Democratic Front emerged victorious, securing 102 seats in the 140-member Assembly.

A significant aspect of the Kerala elections this time has been the emergence of a forward caste leader (V.D. Satheesan), without the support of casteist formations such as the Nair Service Society and the Sree Narayana Dharma Paripalana Yogam, denoting a shift in the politics of Kerala. However, the rise and rise of the Muslim League will be seen by many as bucking this trend. If the new Chief Minister, Mr. Satheesan, is able to detach State politics from the stranglehold of communal and casteist forces, and seize the moment with both hands, it could well usher in a new era in the politics of Kerala.

Few elections to State Assemblies in the past carry this degree of significance as the just concluded ones. Assembly elections this time were held in the backdrop of an assertion by the ruling party at the Centre, of the virtues of the same party being in power at the Centre, and in the States – the so-called 'double engine sarkar'.

Victory for the ruling party at the Centre in the States that went to the polls, were meant to add one more layer to this edifice of the same party ruling the government at the Centre and in the States. West Bengal was the prime target, and ensuring the defeat of Ms. Banerjee had become the single point objective. The campaign was carried out with military precision - less an 'election' than a campaign. Central paramilitary forces were employed extensively to maintain order. The SIR succeeded in the elimination of lakhs of voters, at least some of whom might have fulfilled the voter criteria, and most of whom belonged to the minority. That these tactics succeeded in achieving victory according to a predetermined plan, would suggest that elections are no longer confined to voting without fear or favour.

The implications of this are very considerable. A belief, as also a determination, that the same party should be in power at the Centre and in the States, may appear attractive, but it undermines the logic that people vote according to their conscience, and according to their own logic. In this sense, the elections of 2026 could have a far greater significance than initial outcomes would suggest. It has certain implications as well, for a 'double engine sarkar', often touted as the answer to several of India's problems, especially those faced by the various parties in the country.

Cabinet approves ₹10,000 cr. ATF price stabilisation fund

One-time budgetary support to oil companies is aimed at backing airlines in the backdrop of escalating jet fuel prices due to the West Asia conflict; fund to be offered as interest-free advances

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Seeking to cushion airlines in the backdrop of escalating jet fuel prices due to the West Asia conflict, the Union Cabinet on Wednesday approved a one-time budgetary support of ₹10,000 crore to oil-marketing companies (OMCs) towards a price stabilisation fund.

The budgetary support would be made available to scheduled airlines in India for both domestic and international operations and would be provided in the form of interest-free advances to OMCs.

Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said that the price stabilisation fund would help stabilise (aviation turbine fuel) ATF prices in the backdrop of the West Asia conflict.

"The fund will help stabilise ATF prices for scheduled Indian carriers and will prevent disruption of airline operations while protecting air passengers from fare spikes driven by the geopolitical conflict involving several energy producers," read his social media post.

The budgetary support would function like a self-sustaining revolving fund.

The Cabinet has sought that once the international ATF prices moderate, the differential amount shall be recovered from the oil-marketing companies (OMCs) and returned to the government exchequer.

It would be implemented through an MoU between OMCs and participating airlines and would mandate the latter to procure ATF only from OMCs - either for up to three years or until the advance amount is fully recovered.

Cushioning effect

Petroleum Minister Hardeep Singh Puri says the price stabilisation fund will prevent disruption of airline operations and protect air passengers from fare spikes

- The scheme will be implemented via an MoU between OMCs and participating airlines
- Airlines can procure ATF only from those OMCs — either for up to three years or until advance amount is fully recovered
- Once international ATF prices moderate, differential amount will be recovered from OMCs and returned to govt. exchequer
- The budgetary support would function like a self-sustaining revolving fund

Under-recovery

Officials at the Union Petroleum Ministry had informed on Monday that State-run OMCs were presently incurring an under-recovery of ₹30 on every litre of ATF meant for domestic scheduled carriers.

Further, the government observed that international ATF prices surged nearly 2.5 times from ₹60.5 per litre in March to ₹142 per litre in May.

ATF prices for domestic scheduled carriers were hiked 9% April 1 this year and have been kept unaltered since then.

In fact, Air India, along with its low-cost subsidiary Air India Express and Indigo, together cut down 250 daily domestic flights from June amid rising prices of jet fuel. The move was expected to further escalate airfares.

The government informed that to protect air commuters from a potential sudden price shock, it had capped the ATF prices at ₹75.6 per litre.

'No adequate cushion'

However, the continuing crisis did not offer adequate cushion.

"ATF accounts for nearly 40% of airline operating costs and during periods of extreme fuel volatility, can constitute up to 60% of total operating expenditure," it said.

Crude oil futures hit record high of ₹9,260 per barrel

NEW DELHI

Crude oil prices surged by ₹310 to a fresh record high of ₹9,260 per barrel in futures trade on Wednesday, tracking strong gains in global benchmarks amid the escalating tensions in West Asia. On the MCX, the most-active June crude oil contract climbed by ₹310, or 3.46%, to an all-time high of ₹9,260 per barrel. "Crude oil extended its rally for a third consecutive session on Wednesday as regional escalation intensified overnight," brokerage firm Kotak Neo said. PTI

Refined fuel exports fall to lowest since 2022

NEW DELHI

India's exports of refined petroleum products fell to about 9,30,000 bpd in May, their lowest level since October 2022, as refinery maintenance, changing production priorities and stronger domestic demand curtailed overseas shipments. Exports declined to around 9,30,000 bpd, down to levels last seen when shipments averaged 9,26,000 bpd in October 2022, reflecting a combination of lower refinery throughput and growing focus on supply to the domestic market, according to data analytics firm Kpler. PTI